© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 03 , Issue : 08 | October – December 2017

भारत अमेरिका संबंधों का अध्ययन

Suman Khatri, Assistant Professor, Department of Pol. Science
Saini co-Education College Rohtak

भारत की आज़ादी के बाद अमरीका से उसके संबंध शीतयुद्ध के दौर, अविश्वास और भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर खिंचाव में बंधे रहे हैं|
पिछले कुछ वर्षों से इनमें गर्माहट देखी जा रही है आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर सहयोग में भी इज़ाफ़ा हुआ है|

1947 के बाद से शीत युद्ध की समाप्ति तक भारत-अमेरिका के सम्बन्ध:-

1947 के बाद से शीत युद्ध की समाप्ति तक भारत-अमेरिका के सम्बन्ध, भारत के पाकिस्तान, चीन, और सोवियत संघ के साथ संबंधों के स्वरुप पर आधरित थे।अमेरिका ने हमेशा ही सोवियत संघ के साथ भारत के विशेष संबंधों को शीत युद्ध के सन्दर्भ में देखा। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही भारत के प्रति अमेरिका का नजरिया बदला। शीत युद्धोत्तर काल में भारत के अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद न करने का निर्णय भारत-अमेरिका संबंधों में विवाद का एक प्रमुख विषय रहा है।1998 में सबसे ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी जब अमेरिका ने भारत के परमाणु परिक्षण के बाद कड़े आर्थिक प्रतिबन्ध लागू कर दिए।

पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका द्वारा भारत के खिलाफ कई आर्थिक प्रतिबंध आरोपित कर दिये गये थे। किंतु कुछ समयांतराल पश्चात् ही दोनों देशों के आपसी संबंधन केवल सामान्य बल्कि अभूतपूर्व ढंग से घनिष्ठ हो गये। मार्च 2000 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिंटन द्वारा भारत को यात्रा की गयी यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने माना कि दोनों देश नई सदी की ओर समान ढंग से देखते हैं। कुछ समय बाद ही क्लिंटन प्रशासन द्वारा भारत पर आरोपित अधिकांश प्रतिबंध उठा लिए गये। भारत-अमेरिकी अंतर्निर्भरता को बढ़ाने में अमेरिका स्थित सफल भारतीय समुदाय की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही है। दोनों देशों के मध्य विचारों के नियमित आदान-प्रदान हेतु एक संस्थागत तंत्र भी निर्मित किया गया। सितंबर 2000 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका की यात्रा की गयी। उन्होंने कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया और सार्वभौमिक व राज्य समर्थित आतंकवाद को समाप्त करने हेतु दोनों देशों द्वारा एकजुट प्रयास करने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच आर्थिक-व्यापारिक कार्य-कलापों में भी कई गुना वृद्धि हुई। भारत-अमेरिका के बीच बढ़ती निकटता ने पाकिस्तान के पक्ष में मौजूद अंतरराष्ट्रीय समर्थन की अत्यंत क्षीण बना दिया है।

जनवरी 2000 में स्थापित आतंकवाद के मुकाबले से संबद्ध संयुक्त कार्यदल एक-दूसरे की चिंताओं को और समझने के लिए एक उपयोगी तंत्र साबित हुआ। 31 अगस्त-1 सितम्बर, 2001 तक नई दिल्ली में आयोजित जेडब्ल्यूजीसीटी की छठी बैठक में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की वर्तमान प्रवृत्तियों और अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की गयी। दोनों पक्षों ने आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में विधिप्रवर्तन, वित्तीय और अन्य उपायों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर सहमति व्यक्त की तथा आतंकवाद का मुकाबला करने के बहु-पक्षीय प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया |

भारत-अमेरिका साझीदारी कुछ ऐसे क्षेत्रों में है जो गैर विवादास्पद है। हाल के वर्षों में विदेश नीति के मोर्चे पर अमेरिका के लिए यह एक उपलब्धि रही है। यह कहा जा सकता है कि भारत-अमेरिका संबंधों को अमेरिकी कांग्रेस में दोनो दलों और अमेरिकी नागरिकों के बीच समान रूप से समर्थन हासिल है। मार्च 2000 में बिल क्लिंटन की भारत की यात्रा के साथ प्रारंभ, आज की साझीदारी की स्थिति दोनों देशों के बीच अब तक के सर्वेश्रेष्ठ स्तर पर है।

पिछले तीन राष्ट्रपतियों — क्लिंटन, ओबामा (डेमोक्रेट) एवं बुश (रिपब्लिकन) — सभी ने इन संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कठिन परिश्रम किया है। भारत के नजरिए से देखें तो अगर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों को 'स्वाभाविक साझीदार' करार दिया तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध को एक 'अपरिहार्य साझीदारी' का नाम दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत-अमेरिका नागरिक नाभिकीय समझौते को लेकर अपनी सरकार तक को दांव पर लगा दिया था। उन्होंने इसे अपने 10 वर्ष के शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि घोषित किया था। राष्ट्रपति ओबामा ने भारत-अमेरिका संबंधों को '21 वीं सदी की निर्णायक साझीदारी' बताया था।

भारत-अमेरिका संबंध नए दौर में:-

अब दोनों देशों को एक दूसरे की ताकत-एक दूसरे की जरूरत के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत है अमेरिकी राष्ट्रपति का गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनना |

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा को मिले कम ही वक्त हुआ है, लेकिन दोस्त बनाने में माहिर मोदी कैसे सबको मुरीद बना लेते हैं इसकी बानगी है मोदी-ओबामा मुलाकात। ओबामा जब मोदी को मार्टिन लूथर किंग के स्मारक पर ले गए थे तब दोनों नेता अकेले थे। प्रोटोकॉल की दुहाई देने वाले फॉरेन सर्विस के अफसरान भी नहीं थे। दोनों की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि भारत-अब अमेरिका के साथ बराबरी का रिश्ते बनाना चाहता है। अमेरिका बदले हालात को समझ और स्वीकार कर चुका है।

सितंबर में हुआ प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा छह दशक से अनिश्चितता के जंजाल में फंसे दोनों देशों के रिश्ते को बराबरी के मुकाम पर ले आया है। अब दोनों देशों को एक दूसरे की ताकत-एक दूसरे की जरूरत के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत है अमेरिकी राष्ट्रपति का गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनना। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अथिति बनने का न्यौता स्वीकार करने के साथ ही ओबामा ने रिश्तों में आई नई परिपक्वता को बयान करने के लिए कई प्रतीकों के जरिए कई पैगाम दिए हैं। पहला पैगाम ये है कि अमेरिका अब भारत से अपने रिश्ते को पाकिस्तान से पूरी तरह से अलग करके देखने के लिए तैयार है।

1959 में पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आया। तब आइजेनहावर अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तब से लेकर जिमी कार्टर, निक्सन, क्लिंटन, जॉर्ज बुश तक अमेरिकी राष्ट्रपतियों की भारत यात्रा के साथ पाकिस्तान यात्रा भी हुई। हालांकि 2010 में भी भारत यात्रा के बाद ओबामा पाकिस्तान नहीं गए थे। लेकिन दौरे का वादा किया था, बाद में पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को खोजकर मार गिराने के बाद ओबामा ने दौरा टाल दिया। इस बार ऐसी कोई बात नहीं है। ओबामा ने नवाज शरीफ से बात जरूर की है, लेकिन भविष्य में किसी भी दौरे के लिए वहां हालात सामान्य होने की शर्त भी लगा दी।

बराबरी के रिश्ते को लेकर ओबामा का दूसरा बड़ा कदम बिना वाजिब दस्तावेज अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को तीन साल के वर्क परमिट देने का ऐलान रहा। इस ऐलान का सबसे बड़ा फायदा अमेरिका में रह रहे भारतीयों को ही मिलेगा। ओबामा का ये ऐलान भारतवंशियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीजा ऑन अराइवल के फैसले जैसा ही है, जिसका ऐलान उन्होंने मैडिसन स्क्वॉयर की स्पीच में किया था ।

कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प को भारत और अमेरिका के बीच एक सशक्त और जीवंत संबंध विरासत में मिला है। ऐसी उम्मीद है कि ट्रम्प इस द्विपक्षीय साझीदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। यह इस तथ्य से पूरी तरह स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मैक्सिको एवं मिस्त्र के राष्ट्रपतियों एवं कनाडा तथा इजरायल के प्रधानमंत्रियों के बाद दुनिया के ऐसे पांचवें नेता थे, जिनसे ट्रम्प ने 20 जनवरी, 2017 को अपना पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार बात की थी। 24 जनवरी को हुई मोदी-ट्रम्प बातचीत में पूरी आत्मीयता एवं गर्मजोशी थी, पर ट्रम्प ने अन्य जिन नेताओं के साथ बातचीत की थी, उसके बारे में यही बात नहीं कही जा सकती। दोनों पक्षों द्वारा जारी आधिकारिक बयानों में हालांकि कोई विशेष बात नहीं कही गई लेकिन ट्रम्प शासन काल के प्रारंभिक दिनों के संकेतों से उस वरीयता के साक्ष्य मिलते हैं, जो ट्रम्प भारत-अमेरिका संबंधों को देते हैं। व्हाइट हाउस बयान के अनुसार, ट्रम्प ने जोर देकर कहा था कि अमेरिका भारत को "एक सच्चा मित्र और दुनिया भर की चुनौतियों का सामना करने में एक साझीदार के रूप में देखता है।" बताया जाता है कि दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्र में अपनी साझीदारी को मजबूत बनाने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने दक्षिण एवं मध्य एशिया में सुरक्षा पर भी चर्चा की और "आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में कंधे से कंधा मिला कर लड़ने का संकल्प किया।" मोदी ने ट्वीट किया कि उनकी राष्ट्रपति के साथ "गर्मजोशी से बातचीत हुई और कहा कि दोनों व्यक्तियों ने हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए आगे आने वाले दिनों में घनिष्ठतापूर्वक काम करने पर सहमति जताई।" मोदी और ट्रम्प दोनों ने ही एक दूसरे को राजकीय यात्राओं के लिए आमंत्रित किया। उनकी टेलीफोन पर बातचीत ने रिपब्लिकन प्रशासन के राज में भारत-अमेरिका संबंधों के भविष्य का माहौल तैयार कर दिया।

अमेरिका को चाहिए भारत का बाजार :-

अमेरिका दुनिया की इकलौती महाशक्ति है। कहते हैं कि वो घाटे का सौदा नहीं करता। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमेरिका को भारत का बाजार चाहिए, लेकिन अब भारत भी बराबरी के मंच पर है। लिहाजा मोदी रिश्तों को उस डगर पर ले जा रहे हैं जहां नई साझेदारी का फायदा दोनों देशों को मिले और इसमें पाकिस्तान फैक्टर की कोई जगह न हो।

दो मुल्कों के ताल्लुकात में नेताओं के निजी रिश्ते भी बड़ा किरदार निभाते हैं। कई बार हाथ मिलते ही इतिहास बन जाता है, कई बार सिर्फ हाथ मिलते हैं-दूरी बढ़ जाती है। मोदी और ओबामा पहली बार सितंबर में मिले थे। अब रिश्ते ऐतिहासिक मोड़ पर हैं। मोदी के शपथग्रहण समारोह में शरीफ आए थे, लेकिन कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से बातचीत की पाकिस्तान की जिद के चलते अगस्त में सचिव स्तर की वार्ता टूट गई। लेकिन मोदी भी कूटनीति के कौटिल्य हैं। नए दौर में उन्होंने कुछ इस अंदाज में ओबामा को साथ

मिलाया है कि शरीफ खुद को अलग-थलग महसूस करने लगे हैं। फोन पर ओबामा के सामने कश्मीर राग अलापना भी शरीफ के काम नहीं आया है। सितंबर में दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में भी शरीफ ने कश्मीर राग ही गाया, लेकिन अगले ही दिन अपने 33 मिनट के भाषण में मोदी ने न सिर्फ पाकिस्तान के दोगलेपन को बेपर्दा किया, बल्कि आतंक पर पश्चिमी मुल्कों की सोच को भी आड़े हाथों लिया जो अमेरिका के लिए भी बड़ा पैगाम था।

शरीफ से टेलीफोन पर हुई बातचीत में ओबामा ने जैसी बेरुखी दिखाई है उससे लगता है कि अब वो भी अच्छी तरह से समझने लगे हैं कि आतंकवाद पर कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता है। कश्मीर और आतंक के मुद्दे पर अमेरिका अब पाकिस्तान की बहानेबाजी और झांसे में आने को तैयार नहीं दिखता है। भारत की कीमत पर तो अब ये कतई नहीं होने वाला है।

रणनीतिक साझेदारी की नई दास्तां :-

दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी के पीछे सिर्फ व्यापारिक हित ही नहीं हैं। रणनीतिक साझेदारी की नई दास्तां भी लिखी जा रही है, जिसके केंद्र में चीन भी है। वहीं भारत इस साझेदारी के जरिए कुछ और देशों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करना चाहता है। जनवरी में बराक ओबामा के भारत आने से पहले दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भारत आना है। सितंबर में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भारत का दौरा किया। अमेरिका की तरह चीन भी अपने फलते-फूलते उद्योग के लिए बड़े बाजार की खोज में भारत आया, लेकिन माना जाता है कि अमेरिका के बरअक्स वो भारत से कोई दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का इरादा नहीं रखता।

हकीकत ये है कि दोनों देशों में बहुत पुराना सीमा विवाद है। दोनों देश एक जंग भी लड़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल व्यापारिक रिश्ते ज्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है। इस बाजार के लिए चीन से लेकर जापान और रूस से लेकर अमेरिका तक भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि बड़ा बाजार होने के बावजूद पिछले कुछ साल से भारत इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बड़े बाजार के रुतबे को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन के बरअक्स अमेरिका सिर्फ बाजार की व्राह से ही भारत के करीब नहीं आया है, चीन की बढ़ती व्यापारिक और सैन्य ताकत की काट के लिए एशिया में वो भारत के रूप में बड़ा साझीदार भी तलाश रहा है। लेकिन मोदी-ओबामा से हाथ मिला रहे हैं तो शी चिनफिंग को भी उनके कद के मुताबिक अहमियत दे रहे हैं। मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि जंग से मसलों का हल नहीं निकलता। मेक इन इंडिया से लेकर भारत की तरक्की की जिन योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की है। उसके लिए भी सीमाओं पर लंबे वक्त तक शांति की जरूरत है, लिहाजा अमेरिका से गहरे ताल्लुकात चीन के आक्रामक इरादों की काट की तरह है।

रूस के संदर्भ में भी अमेरिका से बढ़ती नजदीकी का बड़ा पैगाम है। इतिहास के पन्ने कुरेदें तो शीत युद्ध की राजनीति में जब दुनिया पूर्वी ब्लॉक और पश्चिमी ब्लॉक में बंटी थी तब गुटनिरपेक्ष देश होने के बावजूद भारत

सोवियत संघ के ज्यादा करीब रहा। साल 2007 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर भारत आए थे। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी था, लेकिन उसने इस हैसियत का इस्तेमाल हथियार सौदों के मनमाफिक दाम वसूलने और पांचवीं पीढ़ी के विमान जैसी तकनीक देने में अनाकानी करने में किया। ओबामा को गणतंत्र दिवस का न्यौता भेज कर मोदी ने रूस को भी संदेश दिया है कि शक्तिशाली देश के तौर पर भारत के पास रूस अकेला विकल्प नहीं है।

संदर्भ सूची :-

1. फडिया बी एल, "अन्तराष्ट्रीय राजनीति", सहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2012
2. गर्ग सुषमा, "अन्तराष्ट्रीय राजनीति", अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, 2014
3. यादव आर एस, "भारत की विदेशनीति", प्रियसन पब्लिकेशन्स 2013
4. यू. आर. घई एवम के. के घई इंटरनेशनल पोल्टिक्स, न्यू अकेडमिक पब्लिशिंग कम्पनी, जालन्धर 2010
5. अनुपम त्यागी, "भारत अमेरिका सम्बन्ध"
6. पी. एस. जयरामु, इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एंड फारेन पॉलिसी
7. डा बाबू राम पाण्डेय एवम डा राम सूरत पाण्डेय, "युद्ध एवम शांति के मूल तत्व"